

उत्तर प्रदेश में बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर

चर्चा में क्यों?

6 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार गुजरात के बड़ौदा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य के दस ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा से पास अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिये 400 करोड़ रुपए दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- एकीकृत न्यायालय परिसर के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के जनि 10 ज़िलों का चयन किया है, वे हैं- महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्तूरकूट।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यों में अपराधों की अलग-अलग प्रकृतिके अनुसार त्वरति न्याय के लिये अलग-अलग कानूनों से जुड़े अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से जगहों पर काराये के भवनों में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को ही दक्कत होती है। सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में भी दक्कतें आती हैं। इसको देखते हुए अदालतों के लिये एकीकृत कोर्ट परिसर स्थापति करने का नर्णय लिया गया है।
- इसके अलावा एक आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे न्यायालय परिसरों के नर्माण का आदेश दिया गया है।
- राज्य में मुख्यमंत्री के नर्देश पर लोक नर्माण, गृह तथा वधि एवं न्याय वधिाग इस परयोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैबर, मीटिंग हॉल, वडियिो कोर्ट, पॉर्कगि, कैंटीन सहति सभी सुवधिाओं के लिये जगह होगी।
- राज्य में 10 ज़िलों में बनने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणजियकि न्यायालय, वविधि, टर्बियूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगें। यहाँ न्यायालय भवन, अधविकृता चैबर, सभागार के अलावा न्यायधीशों और न्यायकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय कॉलोनी, पार्कगि और फूड प्लाजा भी होगा।